रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर बनी देश की सबसे बड़ी कंपनी

नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल) ने मंगलवार को टीसीएस को पछाड़कर फिर से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी का तमगा हासिल कर लिया। बाजार बंद होने के बाद बीएसई पर आरआइएल का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 7,98,385.98 करोड़ रुपये था। यह टीसीएस के एमकैप 7,85,880.69 करोड़ रुपये से 12,505.29 करोड़ रुपये अधिक है। आरआइएल बीएसई पर 2.33 फीसद मजबूत होकर 1,259.50 रुपये पर बंद हुआ।

वाहन उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से एक है। तकनीक के छात्रों को रोजगार के लिए इस सेक्टर की दक्षता दिए जाने की जरूरत है।
— केनिची आयुकावा, सीईओ एवं एमडी, मारुति सुजुकी इंडिया

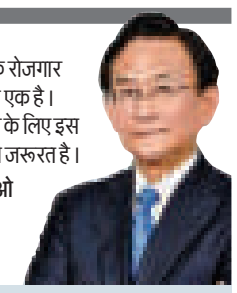

सेंसेक्स	37,318.53	▲ 227.71
निफ्टी	11,222.05	▲ 73.85
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 33,395	▲ ₹377
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹38,300	▲ ₹300
$ डॉलर	₹70.44	▼ ₹0.07
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 70.27	

चुनौती ▶ कहा, चीन आखिरी समय तक ट्रेड वार में अमेरिका से करेगा मुकाबला

ट्रंप की चेतावनी को चीन ने किया दरकिनार

ट्रेड वार नहीं चाहता चीन, लेकिन इससे डरा हुआ भी नहीं है

बीजिंग, प्रेट्र : चीन के और सामानों पर शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के जवाब में चीन ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका आखिरी समय तक लड़ने की चीन की क्षमता को कम करके नहीं आंके। चीन द्वारा अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने के बाद ट्रंप ने कहा था कि वह चीन से आ रहे बाकी बचे सामानों पर भी शुल्क बढ़ा देगा।

चीन ने सोमवार को अमेरिका के 60 अरब डॉलर के और सामानों पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी। इससे पहले अमेरिका ने शुक्रवार को चीन के 200 अरब डॉलर के अतिरिक्त सामानों पर शुल्क बढ़ा दिया था। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि अब चीन के 250 अरब डॉलर के सामानों पर 25 फीसद का शुल्क लग रहा है। हम चीन के बाकी बचे 325 अरब डॉलर के सामानों पर भी शुल्क बढ़ा सकते हैं।

ट्रंप की इस चेतावनी के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि चीन हमेशा कहता रहा है कि शुल्क बढ़ाने से समस्या नहीं सुलझेगी। चीन ट्रेड वार नहीं चाहता है, लेकिन इससे डरा हुआ भी नहीं है। यदि कोई हम पर युद्ध थोपेगा, तो हम अंत तक लडेंगे।

चीन के जवाबी शुल्क के बावजूद ट्रंप कड़े रुख पर कायम

वाशिंगटन : चीन के जवाबी शुल्क के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के सामानों पर शुल्क बढ़ाने के अपने कड़े रुख पर कायम हैं। चीन के जवाबी शुल्क की घोषणा के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा कि व्यापार मोर्चे पर कुछ जवाबी कार्रवाई हो सकती है लेकिन यह बहुत बड़ी नहीं हो सकती है। हम जो अरबों डॉलर शुल्क के रूप में ले रहे हैं, उसका एक छोटा हिस्सा हमारे किसानों को जाएगा, क्योंकि चीन हमारे किसानों के खिलाफ कुछ हद तक जवाबी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि हम अभी, शुल्क के रूप में अरबों डॉलर ले रहे हैं। आगे और भी जबरदस्त शुल्क की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने इसके बाद मंगलवार को किए गए ट्वीट में कहा कि चीन के साथ जो भी समझौता होता, उसकी तुलना में आज हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। दूसरे देश भी हमसे वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे चीन जैसी हालत में पहुंचें।

ट्रंप ने अगले महीने शी व पुतिन से मिलने का संकेत दिया

वाशिंगटन : ट्रंप ने अगले महीने जापान में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन से मिलने का संकेत दिया। शी चिनफिंग से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि जापान में हम जी20 बैठक में मिलने वाले हैं। यह मुलाकात बेहद सफल रहने की उम्मीद है।

चीन पर लगे शुल्क के दायरे से कई सामान होंगे बाहर

वाशिंगटन : ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह चीन पर लगे 25 फीसद शुल्क के दायरे से कई सामानों को छूट देगा। इनमें औद्योगिक उपकरण, वाटर फिल्टरिंग उपकरण, स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेज, स्टेरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप्स आदि शामिल हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय द्वारा 34 अरब डॉलर के सामानों की एक सूची जारी की है, जिनपर 25 फीसद का शुल्क नहीं लगेगा। उधर चीन ने कहा कि अमेरिका चीन से आयात किए जाने वाले कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों पर भी शुल्क नहीं लगाएगा।

अमेरिकी दबाव में चीन की कंपनी गे एप बेचेगी

शंघाई : चीन की कंपनी कुनलुन टेक कंपनी ने कहा कि अमेरिका के दबाव के कारण वह जून 2020 तक गे डेटिंग एप ग्रिंडर बेच देगी। अमेरिकी अधिकारियों ने आशंका जताई है कि एप के आंकड़ों का चीन की सरकार दुरुपयोग कर सकती है।

हुआवे पर चीन का नियंत्रण नहीं

लंदन : चीन की कंपनी हुआवे ने मंगलवार को कहा कि वह एक निजी कंपनी है और चीन की सरकार के नियंत्रण में नहीं है। कंपनी के पश्चिम यूरोपीय कारोबार के वाइस प्रेसिडेंट टिम वाटकिंस ने कहा कि कंपनी चीन की सरकार के साथ सहयोग नहीं करती है, जैसा कि आरोप अमेरिका लगा रहा है।

जेट एयरवेज के सीईओ विनय दुबे ने इस्तीफा दिया

मुंबई, प्रेट्र : नकदी संकट के कारण ठप पड़ गई विमानन कंपनी जेट एयरवेज के सीईओ विनय दुबे ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वह 21 महीने से इस पद पर थे। इसी दौरान वित्तीय कठिनाइयों से पार पाने में नाकाम रहने के बाद 25 साल से आसमान में उड़ रही विमानन कंपनी आखिरकार जमीन पर आ गिरी। इससे एक दिन पहले कंपनी के डिप्टी सीईओ और सीएफओ अमित अग्रवाल ने भी इस्तीफा दे दिया था।

जेट एयरवेज ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि कंपनी के सीईओ विनय दुबे ने कंपनी की सेवा से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों से दिया है। दुबे भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। जेट एयरवेज में अगस्त 2007 में सीईओ के तौर पर जुड़ने से पहले उन्होंने अमेरिका और एशिया में डेल्टा एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस जैसी कंपनियों में कई पदों पर रह चुके थे।

दुबे से पहले कंपनी के सीईओ क्रैमर बॉल थे। उनके इस्तीफा देने के करीब 15 महीने बाद दुबे ने कंपनी की कमान संभाली थी। 15 महीने की इस अवधि में अग्रवाल कार्यवाहक सीईओ थे। दुबे के इस्तीफे की सूचना देने से पहले कंपनी ने मंगलवार को ही बताया कि अग्रवाल ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। अग्रवाल का इस्तीफा 13 मई से ही प्रभावी हो गया है।

- इससे एक दिन पहले कंपनी के डिप्टी सीईओ और सीएफओ अमित अग्रवाल ने भी इस्तीफा दे दिया था
- दोनों शीर्ष अधिकारियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया

पिछले महीने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक राजश्री पाथी, गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशक नसीम जैदी और होल टाइम डायरेक्टर गुआरंग शेट्टी ने भी कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। मार्च में कंपनी के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल और एतिहाद एयरवेज के प्रतिनिधि निदेशक केविन नाइट ने कंपनी को मजबूत करने की योजना के तहत अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल नवंबर में स्वतंत्र निदेशक विक्रम सिंह मेहता और राजन मथाई ने भी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी के बोर्ड में एतिहाद के प्रतिनिधि रोबिन कमार्क, अशोक चावला और शरद शर्मा रह गए हैं।

थोक महंगाई दर अप्रैल में घटकर 3.07 फीसद पर आई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- खाद्य महंगाई का बढ़ना जारी, अप्रैल में पांच महीने के उच्चतम स्तर 7.37 फीसद पर पहुंची
- सब्जियों की महंगाई दर दिसंबर के -19.29 फीसद से बढ़कर अप्रैल में 40.65 फीसद हुई

मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद और फ्यूल के सस्ता होने से थोक महंगाई दर में नरमी आई है। थोक महंगाई दर अप्रैल में मामूली घटकर 3.07 फीसद के स्तर पर आ गई है। हालांकि खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर अब भी ऊंची बनी हुई है। थोक महंगाई दर इस साल मार्च में 3.18 फीसद और फरवरी में 2.93 फीसद थी, जबकि पिछले साल अप्रैल में यह 3.62 फीसद थी।

थोक महंगाई के ताजा आंकड़ों में सबसे चिंता की बात खाद्य वस्तुओं की कीमत में उछाल आना है। सब्जियों के दाम बढ़ने के चलते इस साल अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 7.37 फीसद रही, जबकि मार्च में यह 5.68 फीसद थी। खास बात यह है कि पिछले साल दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर -0.42 फीसद थी और इसके बाद यह लगातार बढ़ते हुए अप्रैल में पांच माह के उच्चतम स्तर पर आ गई है। इसी तरह सब्जियों की महंगाई दर भी दिसंबर 2018 के बाद लगातार बढ़ रही है। उस समय यह -19.29 फीसद थी, जबकि अप्रैल में यह बढ़कर 40.65 फीसद हो गई है। खाद्य वस्तुओं में आलू की महंगाई दर -17.15 फीसद रही, जबकि प्याज की -3.43 फीसद और फलों की -3.43 फीसद रही। हालांकि दालों की महंगाई दर 14.32 फीसद रही।

'फ्यूल एंड पावर' श्रेणी की महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है और यह मार्च के 5.41 फीसद के स्तर से घटकर अप्रैल में 3.84 फीसद पर आ गई है। डीजल की महंगाई दर मार्च में 7.33 फीसद थी, जो अप्रैल में घटकर 3.24 फीसद रह गई है, जबकि पेट्रोल की महंगाई दर इस अवधि में 1.78 फीसद से घटकर 1.74 फीसद के स्तर पर आ गई है। इस श्रेणी में एलपीजी की महंगाई दर बढ़कर 11.48 फीसद हो गई, जबकि मार्च में यह 0.94 फीसद थी। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की महंगाई में भी गिरावट दर्ज की गई और यह मार्च के 2.16 फीसद के स्तर से घटकर अप्रैल में 1.72 फीसद पर आ गई है।

थोक महंगाई की दर हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की मुख्य नीतिगत ब्याज दरों को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आरबीआइ यह दर तय करने के लिए खुदरा महंगाई को संज्ञान में लेता है। खुदरा महंगाई का आधिकारिक आंकड़ा एक दिन पहले ही जारी हुआ था और अप्रैल में यह मामूली बढ़कर 2.92 फीसद पर पहुंच गई है।

भारत ने अमेरिका पर जवाबी शुल्क की समय सीमा फिर बढ़ाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने एक बार फिर अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की समय सीमा बढ़ा दी। अमेरिका के 29 उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की समय सीमा को इस बार बढ़ाकर अगले महीने की 16 तारीख कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अमेरिका से आयात किए जाने वाले चिह्नित उत्पादों पर बढ़ा हुआ आयात शुल्क लगाने की समय सीमा को 16 मई से बढ़ाकर इस साल 16 जून कर दिया गया है।

सरकार ने जून 2018 के बाद से इस समय सीमा को कई मर्तबा बढ़ाया है। कुछ खास अल्यूमीनियम और स्टील उत्पादों पर अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाने की कार्रवाई करने के बाद सरकार ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया था।

सरकार ने शुल्क बढ़ाने की समय सीमा को तब बढ़ाया है, जब अमेरिका ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) के तहत भारतीय व्यापारियों को व्यापार में दी जा रही छूट हटाने का फैसला किया है। इस छूट के हटने से भारत से अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा।

बिचौलिया मुक्त गेहूं खरीद से खुले बाजार में कीमत में हुआ सुधार

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

- ई-प्रोक्यूरमेंट सॉफ्टवेयर से रुकी उत्तर प्रदेश की गेहूं खरीद में कमीशनखोरी
- निजी कंपनियों की खरीद से भी बाजार में सुधार का रुख

खुले बाजार में कीमतों में हुए सुधार के चलते गेहूं की सरकारी खरीद पर असर पड़ना तय है। उत्तर प्रदेश की सरकारी खरीद में बिचौलियों के बाहर हो जाने से भी यहां बाजार प्रभावित हुआ है। सभी गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक बोला जा रहा है। सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में निजी कंपनियों की ओर से खरीद होने से भी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं।

उत्तर प्रदेश में निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को गेहूं स्टॉक करने का मौका नहीं मिल पाया है। इसके चलते निजी कंपनियां और बड़े उपभोक्ता प्रतिष्ठानों की खरीद हो रही है। इसका असर बाजार में दिखने लगा है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की सरकारी एजेंसियां खरीद खुद करने के बजाय आढ़तियों के मार्फत करती हैं। दोनों राज्यों में खरीद अंतिम चरण में पहुंच गई है, जहां किसानों के पास गेहूं का स्टॉक नहीं है। इसके मद्देनजर निजी कंपनियों ने अपने लिए गेहूं की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश की मंडियों का रुख किया है।

उत्तर प्रदेश में 10 एजेंसियां सरकारी खरीद करने में जुटी हुई हैं। लेकिन खरीद प्रणाली चाकचौबंद होने से निजी व्यापारी इसमें घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि ई-प्रोक्यूरमेंट प्रणाली से यह सब संभव हो सका है। खरीद से पहले किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसमें जमीन का रकबा और उसमें बोई गई फसल का सही-सही ब्योरा देना होता है। कुछ किसानों के आंकड़ों की तस्दीक भी कराई जाती है। आलोक कुमार ने बताया कि पिछले साल की खरीद में कुल 11 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था। उन्हें उम्मीद है कि सरकारी एजेंसियों के सक्रिय हस्तक्षेप से खुले बाजार में भाव मजबूत हुए हैं जिसका लाभ किसानों को मिल सकता है।

प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में खुले में गेहूं 1800 रुपये से लेकर 1850 रुपये तक बिक रहा है। निजी कंपनियों की खरीद से भाव में लगातार सुधार हो रहा है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार 55 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने की कोशिश हो रही है।

डब्ल्यूटीओ का अपीलीय तंत्र दिसंबर तक हो सकता है पंगु

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विकासशील देशों ने अपीलीय तंत्र में रिक्तियों को भरने की जरूरत बताई
- दो दिवसीय मंत्रीस्तरीय बैठक के बाद 17 प्रतिभागी देशों ने की अपील

विश्व के 17 विकासशील देशों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अपीलीय निकाय में रिक्तियों को भरे जाने की अपील की है। उनका कहना है कि मौजूदा गतिरोध के चलते डब्ल्यूटीओ का विवाद निस्तारण तंत्र दिसंबर तक पूरी तरह पंगु बन सकता है। विकासशील देशों ने यहां दो दिवसीय मंत्रीस्तरीय बैठक के समापन पर यह अपील की। उन्होंने विकास और समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को मजबूत बनाने और उसके लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया।

बैठक के बाद जारी घोषणापत्र पर हालांकि सिर्फ 17 देशों ने ही हस्ताक्षर किए, जबकि पांच देशों ने इस 13 सूत्रीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना मुनासिब नहीं समझा। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य राष्ट्रों ने कहा कि डब्ल्यूटीओ का विवाद निस्तारण तंत्र बेहद महत्वपूर्ण है और मौजूदा गतिरोध के चलते यह दिसंबर 2019 तक पूरी तरह पंगु बन सकता है। इसलिए ये देश डब्ल्यूटीओ सदस्यों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए रचनात्मक ढंग से बातचीत करने और अविलंब अपीलीय निकाय की रिक्तियों को भरे जाने की अपील करते हैं। घोषणापत्र में विवाद निस्तारण तंत्र की कार्यप्रणाली से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत जारी रखने को कहा गया है।

गौरतलब है कि अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के अपीलीय तंत्र में नियुक्तियों की राह में रोड़ा अटका दिया है। इस तंत्र के काम करने के लिए तीन सदस्यों का कोरम पूरा होना जरूरी है और इसकी मियाद 10 दिसंबर को पूरी हो रही है। ऐसी स्थिति में यह तंत्र निष्क्रिय हो जाएगा। भारत ने इस मंत्री स्तरीय बैठक के पहले ही दिन यह मुद्दा उठाया था।

घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि विशेष बर्ताव के संबंध में प्रावधान विकासशील देशों का अधिकार है और डब्ल्यूटीओ के मौजूदा व भविष्य के समझौतों में इन्हें न सिर्फ सुरक्षित रखना चाहिए, बल्कि इन्हें मजबूत भी बनाना चाहिए। साथ ही सबसे पिछड़े देशों के मुद्दों को भी प्राथमिकता के साथ देखा जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ के विशेष प्रावधानों के तहत विकासशील देशों को कृषि क्षेत्र के लिए घरेलू मदद जैसे लाभ मिलते हैं। साथ ही उन्हें बाध्यकारी समझौतों को लागू करने के लिए भी अधिक समय दिया जाता है। घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि डब्ल्यूटीओ के सुधार की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। साथ ही विकास में भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सेबी ने दिया था रैनबैक्सी से 403 करोड़ वसूलने का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (एफएचएल) ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने उसे रैनबैक्सी लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह से 403 करोड़ रुपये वसूलने को कहा है। आरोप है कि उन्होंने एफएचएल व उसकी सहायक कंपनी फोर्टिस हॉस्पिटल लिमिटेड के रुपये को डायवर्ट किया था। जापान की दवा बनाने वाली कंपनी दाईची सैंक्यो द्वारा सिंह ब्रदर्स व उनकी फर्म के खिलाफ दायर एक मामले में एफएचएल ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में एफएचएल ने कहा कि सेबी ने 17 अक्टूबर 2018 को दिए अपने एक आदेश में सिंह ब्रदर्स और उनकी प्रमोटर कंपनियों से तीन महीने के भीतर ब्याज सहित 403 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

अमेरिका में अरबिंदो फार्मा व अन्य कंपनियों पर भी मुकदमा

- अमेरिका में दवाओं की कीमतें तय करने में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों का आरोप
- आरोपित कंपनियों में कैडिला हेल्थकेयर की इकाई जायडस फार्मास्युटिकल्स का नाम भी

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका में दवाओं की कीमतें तय करने में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के आरोप में दिग्गज दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा समेत अन्य कंपनियों के खिलाफ दूसरा मुकदमा दायर किया गया है। अरबिंदो फार्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि कनेक्टिकट के अटॉर्नी जनरल और विभिन्न अमेरिकी राज्यों के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने 10 मई 2019 को संघीय अदालत में दूसरा मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि अमेरिका जेनेरिक दवा उद्योग में अरबिंदो और अन्य कंपनियों ने कीमत तय करने और ग्राहकों को आवंटन करने में प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया है।

मुकदमे में कहा गया है कि राज्यों के अटॉर्नी जनरल की दूसरी कार्रवाई में अतिरिक्त पक्षों और उत्पादों को शामिल किया गया है। जिनका पहले मुकदमे में जिक्र नहीं किया गया था। अरबिंदो फार्मा ने कहा कि कंपनी दूसरे मुकदमे की समीक्षा कर रही है। हमें उम्मीद है कि निर्धारित समय में आरोपों के खंडन से जुड़े दस्तावेज संघीय अदालत में जमा करेंगे। कंपनी ने कहा कि इस समय आशा करते हैं कि इन मामलों का कंपनी के परिचालन और कारोबारी नतीजों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरबिंदो और अन्य कंपनियों पर इससे पहले दिसंबर 2016 में संघीय अदालत में पहला मुकदमा दायर किया गया था। इसमें कंपनियों पर दवाओं की कीमत निर्धारित करने में साठगांठ का आरोप लगाया था।

इस बीच, औषधि कंपनी कैडिला हेल्थकेयर ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि अमेरिकी राज्यों द्वारा जेनेरिक दवाएं बनाने वाली कुछ कंपनियों के खिलाफ दायर मुकदमे में उसकी इकाई जायडस फार्मास्युटिकल्स का नाम भी शामिल है। जायडस फार्मास्युटिकल्स, कैडिला हेल्थकेयर की अमेरिकी इकाई है। कैडिला हेल्थकेयर ने कहा कि इस मामले का कंपनी के कामकाज और वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं होगा। बयान के अनुसार जायडस बहुत ईमानदारी से अपना कारोबार करती है।

मुनाफा

बीएसई का सेंसेक्स 227.71 अंकों की तेजी के साथ 37,318.53 पर बंद, एनएसई का निफ्टी 73.85 अंक उछलकर 11,222.05 पर स्थिर हुआ

बाजार में नौ दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक

मुंबई, प्रेट्र : बाजार में नौ दिनों से जारी गिरावट के सिलसिला पर मंगलवार को ब्रेक लग गया और शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक तेजी बनाकर बंद हुए। खुदरा महंगाई दर कम रहने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की मुख्य ब्याज दर में कटौती की उम्मीद में वित्तीय और ऊर्जा शेयरों में भारी लिवाली देखी गई।

बीएसई का सेंसेक्स 227.71 अंकों की तेजी के साथ 37,318.53 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 73.85 अंकों की तेजी के साथ 11,222.05 पर बंद हुआ। इससे पहले के नौ सत्रों में सेंसेक्स में कुल 1,940.73 अंकों की गिरावट रही थी। सेंसेक्स में सन फार्मा में सर्वाधिक 5.87 फीसद तेजी रही। भारती एयरटेल, वेदांता, इंडसइंड बैंक, एसबीआइ और आरआइएल में भी 5.40 फीसद तक उछाल दर्ज किया गया। दूसरी ओर टीसीएस में सर्वाधिक 1.72 फीसद गिरावट रही। संकट ग्रस्त विमानन कंपनी जेट एयरवेज में 7.42 फीसद गिरावट रही।

सेक्टरों के लिहाज से टेलीकॉम, ऊर्जा और कैपिटल गुड्स में 2.81 फीसद तक तेजी रही। खुदरा महंगाई दर अप्रैल में 2.92 फीसद दर्ज की गई है और यह आरबीआइ के लक्षित स्तर से नीचे है। इससे बाजार में उम्मीद जगी है कि आरबीआइ आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य नीतिगत दरों में कटौती कर सकता है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर भी अप्रैल में घटकर 3.07 फीसद रही। एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में अमेरिका-चीन तनाव के असर से मोटे तौर पर गिरावट का रुझान देखा गया।

सुरक्षित निवेश के रूप में मांग बढ़ने से सोना मजबूत

- सोना 377 रुपये उछलकर 33,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा
- चांदी 300 रुपये चढ़कर 38,300 रुपये प्रति किलोग्राम की हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय ट्रेड वार के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में आकर्षण बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 377 रुपये उछलकर 33,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी बढ़ाए जाने के कारण चांदी भी 300 रुपये चढ़कर 38,300 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई।

सराफा कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय मांग बढ़ने के साथ ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव गहराने से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने का आकर्षण बढ़ गया। इसके कारण पीली धातु की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिका द्वारा चीन के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए जाने के बाद चीन ने भी सोमवार को कहा कि वह अमेरिका के करीब 60 अरब डॉलर के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाएगा। न्यूयॉर्क में सोने में 1,298 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 14.83 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 377 रुपये उछलकर 33,395 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतने ही उछाल के साथ 33,225 रुपये प्रति 10 ग्राम का हो गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी हालांकि 26,500 रुपये प्रत्येक के भाव पर कायम रही। चांदी हाजिर 300 रुपये चढ़कर 38,300 रुपये, जबकि वीकली डिलीवरी 267 रुपये उछलकर 37,557 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 1,000 रुपये बढ़कर 80,000 रुपये खरीद और 81,000 रुपये बिक्री के स्तर पर पहुंच गई।

मौसम विशेष

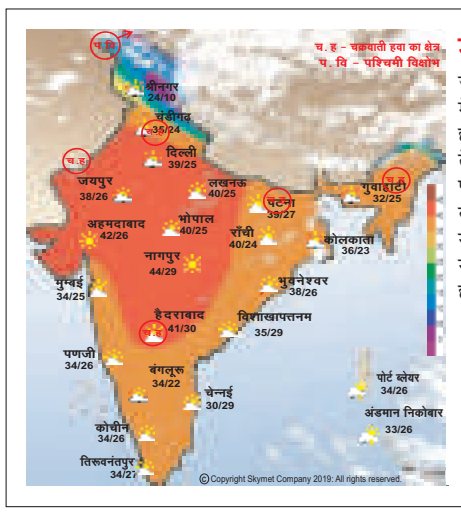

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होगी। कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी तथा हल्की वर्षा होगी। दिन गर्म बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/26/व	अहमदाबाद	42/25/आंबा
कोलकाता	37/24/सा	बड़ोदा	42/25/सा
चेन्नई	39/28/आंबा	नागपुर	45/29/आंबा
हैदराबाद	40/29/सा	इन्दौर	41/27/सा
बंगलूरू	35/21/सा	रांची	44/26/सा
त्रिवेन्द्रम	34/27/आंबा	पटना	42/29/आंबा
गुवाहाटी	31/24/सा	जमशेदपुर	44/28/व
गंगटोक	17/07/आंबा	पुणे	36/23/आंबा